भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1831

13 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र का कार्य निष्पादन

1831. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

डॉ. के. जयकुमार :

डॉ. ए. चेल्लाकुमार :

श्री टी. एन. प्रथापन :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से अब तक इस्पात उत्पादन और घरेलू खपत के लिए निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का पृथक रूप से वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में इस्पात की खपत बहुत कम है और यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में इस्पात के प्रति व्यक्ति उपयोग में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2014 से अब तक देश में इस्पात के आयात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्य और उत्पादन अलग-अलग कंपनियों द्वारा बाजार की गतिशीलता और वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसी प्रकार, देश में इस्पात की खपत निर्माण, अवसंरचना, इंजीनियरिंग और व्हाइट गुड्स, ऑटोमोटिव और रक्षा जैसे इस्पात की खपत वाले क्षेत्रों के विकास पर निर्भर है। सरकार देश में इस्पात उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए इस्पात उद्योग को सुविधा प्रदान करती है। वर्ष 2013-14 से देश में इस्पात और खपत का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्रूड इस्पात का कुल उत्पादन (एमटी में)	तैयार इस्पात की कुल खपत (एमटी में)
2013-14	81.69	74.09
2014-15	88.98	76.99
2015-16	89.79	81.52
2016-17	97.94	84.04
2017-18	103.13	90.71
2018-19	110.92	98.71
2019-20	109.14	100.17
2020-21	103.54	94.89
2021-22	120.29	105.75
2022-23	127.20	119.89
स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) ; एमटी = मिलियन टन		

(ख) और (ग): भारत तैयार इस्पात का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, देश में इस्पात की खपत 119.89 एमटी तथा इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 86.7 कि.ग्रा. थी। सरकार देश में इस्पात उत्पादन और खपत को बढावा देने के लिए इस्पात उद्योग को सुविधा प्रदान करती है। उस दिशा में, सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 लागू की है जिसमें वर्ष 2030-31 तक इस्पात की खपत को 230 एमटीपीए तक और इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत को 158 कि.ग्रा. तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। सरकार द्वारा गतिशक्ति मास्टर प्लान, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल तथा सरकार की अन्य फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित किए जाने और अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ाने पर बल दिए जाने से देश में इस्पात की मांग तथा खपत को गति मिलती है। आवास और निर्माण क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस्पात मंत्रालय ने घरों और लौंग स्पैन सड़क पुलों के निर्माण हेतु इस्पात-प्रधान डिजाइनों को विकसित करने के लिए उद्योग और तकनीकी संस्थानों (आईआईटी/एनआईटी) के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है।

(घ): वर्ष 2014 से देश में इस्पात के आयात का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	तैयार इस्पात का कुल आयात (एमटी में)
2013-14	5.45
2014-15	9.32
2015-16	11.71
2016-17	7.22
2017-18	7.48
2018-19	7.84
2019-20	6.77
2020-21	4.75
2021-22	4.67
2022-23	6.02
स्रोत : जेपीसी ; एमटी = मिलियन टन	

***